दिल्ली की झुग्गी-पुनर्वास नीति 2026: कटऑफ 2006 से 2025, और “पहले घर, फिर विस्थापन” की शर्त

राष्ट्रीय/शहरी नीति | DUSIB • पुनर्वास • GS-I/GS-II | समाचार-संदर्भ: 4 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 4 नवंबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

दिल्ली की जल्द अधिसूचित होने वाली **झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास नीति 2026** पर द हिंदू में 4 नवंबर 2026 को विश्लेषण (सुरभि सचदेवा) प्रकाशित हुआ। पृष्ठभूमि: दिल्ली विधानसभा ने **11 अगस्त 2026** को **DUSIB (संशोधन) विधेयक 2026** पारित कर झुग्गी-झोपड़ी (JJ) क्लस्टरों की पहचान की कटऑफ तारीख **1 जनवरी 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025** कर दी — 19 वर्षों से अपरिवर्तित कटऑफ के कारण बड़ी संख्या में परिवार दायरे से बाहर थे। केंद्र का दावा है कि नई **Delhi Slum and JJ Cluster Rehabilitation and Relocation Policy, 2026** (जो 2015 की नीति का स्थान लेती है) से लगभग **चार लाख परिवारों** को लाभ होगा; केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जून 2026 को DDA और DUSIB को पाँच JJ क्लस्टरों के पुनर्वास के टेंडर 45 दिनों में जारी करने को कहा था। लेख का केंद्रीय प्रश्न: क्या पुनर्वास की इकाई सिर्फ “फ्लैट” है, या परिवार का सम्पूर्ण शहरी जीवन — काम, स्कूल, देखभाल, पड़ोस और आवागमन?

PCSMANTRA.COM

कानून में बदलाव: कटऑफ 2006 → 2025

शहरी विकास मंत्री आशीष सूद द्वारा प्रस्तुत **DUSIB (संशोधन) विधेयक 2026** मानसून सत्र में 11 अगस्त 2026 को पारित हुआ। प्रमुख प्रावधान: JJ क्लस्टरों की पहचान की कटऑफ तारीख 1 जनवरी 2006 से आगे बढ़ाकर **1 जनवरी 2025** — सरकार के अनुसार इससे "इन-सीटू" (उसी स्थान पर) पुनर्वास का समेकित विकास-मॉडल संभव होगा, ताकि लोगों की नौकरियाँ जारी रहें। 2006 की कटऑफ 19 वर्ष से अपरिवर्तित थी और नई बस्तियों को पात्रता से बाहर रखती थी।

नीति 2026: क्या बदलता है

Delhi Slum and JJ Cluster Rehabilitation and Relocation Policy, 2026 2015 की नीति की जगह लेती है और कवरेज बढ़ाती है; केंद्र के अनुसार लाभार्थी लगभग **4 लाख परिवार**। 16 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने नीति को अंतिम रूप बताते हुए **DDA और DUSIB को 45 दिनों में पाँच JJ क्लस्टरों के पुनर्वास टेंडर** जारी करने और दिल्ली सरकार को नीति शीघ्र अधिसूचित करने को कहा। नियमावली औपचारिक अधिसूचना के बाद लागू होगी — इसलिए नीति-पाठ की हर धारा का वास्तविक प्रभाव अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा।

न्यायिक ढांचा: आवास = आजीविका से जुड़ा अधिकार

दशकों से भारतीय अदालतें यही कहती आई हैं: **Olga Tellis** में सुप्रीम कोर्ट ने आवास के स्थान को आजीविका से जोड़ा; **सुदामा सिंह** और **अजय माकन** मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निवासियों को मात्र "अतिक्रमणकारी" न मानें — अर्थपूर्ण भागीदारी, सर्वेक्षण और उचित पुनर्वास आवश्यक है। लेख के अनुसार नई नीति को एक प्रवर्तनीय नियम से शुरू होना चाहिए: **"पहले इन-सीटू, अंतिम उपाय विस्थापन" (in-situ first, relocation last)**। जहाँ स्थानांतरण अपरिहार्य हो, तब तक कोई विध्वंस नहीं जब तक सुविधा-युक्त घर तैयार न हो — उचित आजीविका-क्षेत्र (livelihood catchment) में, पहले दिन से सार्वजनिक परिवहन, स्कूल और स्वास्थ्य-सुविधाएँ चालू हों।

आगे देखने योग्य

अधिसूचना के बाद: पात्रता-सत्यापन की प्रक्रिया (सर्वेक्षण, दस्तावेज़), टेंडरों की गति, स्थानांतरण-स्थलों की दूरी और सुविधाएँ, और किराया/स्वामित्व शर्तें। इतिहास गवाह है कि दूरस्थ विस्थापन से आय और शिक्षा दोनों टूटते हैं — इसलिए "पुनर्वास की इकाई फ्लैट नहीं, परिवार का शहरी जीवन" वाला मानक ही नीति की कसौटी होगा।

घटनाक्रम

- **2015:** दिल्ली की पूर्व JJ पुनर्वास नीति (अब प्रतिस्थापित)
- **16 जून 2026:** गृह मंत्री: नई नीति 2026 को अंतिम रूप; 4 लाख परिवार लाभार्थी; 45 दिनों में 5 क्लस्टरों के टेंडर का निर्देश
- **10 अगस्त 2026:** UD मंत्री आशीष सूद ने DUSIB (संशोधन) विधेयक विधानसभा में पेश किया
- **11 अगस्त 2026:** विधानसभा ने विधेयक पारित किया: कटऑफ 1 जनवरी 2006 → 1 जनवरी 2025
- **4 नवंबर 2026:** द हिंदू विश्लेषण: "पहले घर, फिर विस्थापन" सिद्धांत अपनाए बिना नीति अधूरी

PCSMANTRA.COM

परीक्षा के लिए महत्त्व

मेन्स (GS-I/GS-II): शहरी गरीबी और आवास; पुनर्वास-नीति का मानवीय ढांचा; न्यायिक अधिकार-विस्तार (आवास-आजीविका संबंध); केंद्र-राज्य समन्वय।
प्रिलिम्स: DUSIB; कटऑफ परिवर्तन (2006→2025); 2026 नीति बनाम 2015; Olga Tellis; DDA।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. "पुनर्वास की इकाई फ्लैट नहीं, परिवार का शहरी जीवन है।" दिल्ली की नई झुग्गी-पुनर्वास नीति के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)

भूमिका में
कटऑफ 2025 तक बढ़ना और 4 लाख परिवारों का लाभ-अनुमान स्वागतयोग्य, किंतु पुनर्वास की सफलता केवल घर की संख्या से नहीं मापी जा सकती।

मुख्य भाग में
न्यायिक मानक: Olga Tellis (आवास-आजीविका संबंध), सुदामा सिंह/अजय माकन (भागीदारी, सर्वेक्षण, उचित पुनर्वास)। "In-situ first, relocation last" — विस्थापन अपरिहार्य हो तो पहले सुविधा-युक्त घर तैयार हो: परिवहन, विद्यालय, स्वास्थ्य पहले दिन से। दूरस्थ विस्थापन के ज्ञात परिणाम: आय-क्षति, स्कूल छुटना, सामाजिक जाल का टूटना। क्रियान्वयन की कसौटी: सर्वेक्षण की पारदर्शिता, टेंडर-गति, स्थान-दूरी, सामूहिक भागीदारी।

निष्कर्ष में
कटऑफ-विस्तार आवश्यक सुधार है; किंतु नीति तभी सफल होगी जब पुनर्वास को आजीविका-निरंतरता के साथ मापा जाए — घर वहीं, जीवन भी वहीं।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. DUSIB (संशोधन) विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: इसमें JJ क्लस्टरों की कटऑफ तारीख 1 जनवरी 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 की गई।
कथन-II: यह विधेयक दिल्ली विधानसभा में 11 अगस्त 2026 को पारित हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

(b) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(c) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

(d) न तो कथन-I, न ही कथन-II सही है

PCSMANTRA.COM

▶ **उत्तर और व्याख्या**

प्रश्न 2. दिल्ली की झुग्गी-पुनर्वास नीति 2026 और न्यायिक मानकों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

(a) नई नीति 2015 की नीति का स्थान लेती है और केंद्र के अनुसार लगभग 4 लाख परिवारों को लाभ देगी

(b) Olga Tellis मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आवास को आजीविका से अलग माना

(c) नई नीति में सभी JJ क्लस्टरों का अनिवार्य विस्थापन शहर से बाहर किया जाएगा

(d) नीति पहले ही अधिसूचित होकर पूर्णतः लागू हो चुकी है

▶ **उत्तर और व्याख्या**

स्रोत

1. **द हिंदू: Delhi needs better slum rehabilitation policy — सुरभि सचदेवा (4 नवंबर 2026)**
2. **द ट्रिब्यून: Delhi Assembly clears Bill to advance cut-off date (11 अगस्त 2026)**
3. **द हिंदू: New slum rehabilitation policy to benefit 4 lakh families finalised — Amit Shah (16 जून 2026)**
4. **द प्रिंट/PTI: Delhi Assembly passes bill to change cut-off date (11 अगस्त 2026)**

PCSMANTRA.COM